प्रेस नोट **16 फरवरी, 2015**

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं विधायक श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज मीडिया को निम्नलिखित बयान जारी किया ;

'श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लापरवाह शासन व बेपरवाह प्रशासन की क्रूरर अनदेखी ने देश के करोड़ों किसानों को भयंकर यूरिया खाद संकट झेलने को मजबूर कर दिया है।

रबी की फसल के पिछले पांच महीने में पूरे देश में यूरिया खाद की कालाबाजारी, पुलिस द्वारा किसानों पर जगह-जगह लाठीचार्ज, यूरिया के भंडारों को भीड़ द्वारा लूटा जाना तथा ठिठुरती सर्दी में घंटों तक पुलिस थानों में यूरिया का बांटा जाना आये दिन की व्यवस्था तथा अखबार की सुर्खियां बन गया है। किसान पीस रहा है और दूसरी ओर 'सियासी छलावे' तथा 'राजनीतिक जुमले' घढ़ने में व्यस्त मोदी सरकार कुंभकरणी नींद सो रही है।

अब यह स्पष्ट है कि मानव निर्मित यूरिया खाद संकट देश के दो कारणों से पैदा हुआ ;
पहला : जून से अक्तूबर, 2014 के बीच के महत्वपूर्ण रबी की फसल बुआई के समय भारत सरकार द्वारा मात्र 11.37 लाख टन यूरिया का आयात कर पाना, जो पिछले साल यानी 2013 में 43.82 लाख टन था। (पिछले साल के मुकाबले में मात्र एक तिहाई आयात)
दूसरा : भाजपा सरकार द्वारा भारतीय यूरिया उत्पादकों को 30 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी न देना यानी की कुल सब्सिडी का 95 प्रतिशत हिस्सा न देना है तथा कई यूरिया उद्योगों का बंद हो जाना।

हम श्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण वायदा (कालेधन की वापसी के अलावा) किसानों को उनकी लागत पर पचास प्रतिशत मुनाफा देकर किसान की फसल का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना था। सत्ता में आते ही श्री मोदी ने इसे 'राजनीतिक जुमला' समझ अपने वायदों की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। नतीजा यह है कि आज कृषि उत्पादों की कीमतों में औनी-पौनी गिरावट आई है। बासमती चावल की कीमत 2013-14 के 6000-6500 रुपया प्रति क्विंटल से घटकर 2014-15 में 3200-3300 रुपया प्रति क्विंटल है। अच्छे किस्म के चावल 1121 एवं 1509 की कीमतें पिछले साल 4400-4800 रुपया प्रति क्विंटल से घटकर 2200-2400 रुपया प्रति क्विंटल रह गई हैं। कपास की कीमत भी 2013-14 के 5300-5500 रुपया प्रति क्विंटल के मुकाबले 2014-15 में घटकर 3800-4000 रुपया प्रति क्विंटल रह गई हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी कम है।

जले पर नमक छिड़कते हुए मोदी सरकार ने जबरन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी कर दिया है। कृषि क्षेत्र के व्यापक कुप्रबंधन के चलते 2014-15 में गेहूं, चावल व मक्की के निर्यात में 29 प्रतिशत यानी कि 135 लाख टन तक गिरावट होने की संभावना है। यहां तक कि कृषि क्षेत्र की बुआई भूमि में 33.22 लाख

हैक्टयेर की गिरावट आई है यानी यह भूमि जोती ही नहीं जा सकी।

परिणाम यह होगा कि कांग्रेस सरकार के एक दशक के शानदार शासन के बाद साल 2014-15 में कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज होगी'।

रणदीप सिंह सुरजेवाला
प्रवक्ता एवं विधायक।